Pre- and Post-STI Policy Impact: Information Analytics



Dr. Venkatesh Dutta, Babasaheb Bhimrao Ambedkar University, Lucknow

In the session on impact of STI Policy, Dr. Sanjay Mishra, Scientist, Department of Science and Technology spoke on less coverage of science in newspapers and magazines and suggested that science communication should be introduced in the undergraduate curriculum. In his talk, Dr. Venkatesh Dutta, Babasaheb Bhimrao Ambedkar University, Lucknow said that cultural theory or grounded reality is mostly ignored while shaping science policies. There is a need to come up with customised policies, he said.

दैनिक जागरण, 09 फरवरी 2020

गोमती को मिलेगी अपनी जमीन

एनजीटी के आदेश पर नदी भूमि चिह्नित करने का आदेश



राकेशनाथ, शाहजहांपुर के आगे गोमती नदी इस स्थिति में पहुंच गई है • जागरण

लखनऊ • शाहजहांपुर

पीलीभीत के माधोटांडा से निकलकर प्रदेश के दर्जनभर जिलों से बहती हुई गोमती भले ही लगभग 960 किमी का सफर तय करती है। लेकिन, विडंबना यह कि इस पूरे प्रवाह क्षेत्र में गोमती अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ती नजर आती है। उद्गम से कुछ दूर बाद से ही नदी अपने अस्तित्व के लिए जंग लड़ती दिखाई देती है। यही नहीं, कई स्थानों पर तो इसकी धार के बीचोंबीच खेती होती देखी जा सकती है। अतिक्रमण के चलते नदी की कई जगह या तो धार गायब हो जाती है या पतली धार के रूप में यह सिमटी दिखाई देती है। नदी को बचाने की दिशा में अब जीत हासिल हुई है।

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश पर अब नदी भूमि को चिह्नित किया जाएगा। नदी संरक्षण के लिए लगातार आवाज उठाने वाले डॉ. वेंकटेश दत्ता बताते हैं कि राजस्व परिषद द्वारा 29 जनवरी को पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, सुलतानपुर व जौनपुर जहां से गोमती होकर बहती है, डीएम को आदेश दिया गया है कि वह नदी भूमि चिह्नित कर अभिलेखों में दर्ज कराएं।

पर्यावरण संरक्षण

32 शहरी नाले गिरने के कारण गोमती में कटीलहो जाती है गोमती

960 किलोमीटर का सफर तय कर माधोटांडा से जौनपुर तक बहती है गोमती नदी

28 सहायक नदियां गोमती को देती हैं जीवन, लेकिन वे भी हैं अतिक्रमण की चपेट में

सहायक नदियां भी जी उठेंगी

कहने को तो गोमती को 28 सहायक नदियां जीवन देती हैं। लेकिन, सहायक नदियां भी सदा अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं। यही कारण है कि लखनऊ पहुंचते-पहुंचते गोमती की स्थिति खराब हो जाती है। एक तरफ पानी की कमी, दूसरी ओर नदी में गिरने वाले करीब 32 शहरी नालों से होने वाले प्रदूषण से नदी नाले के समान दिखती है।

सादा धान पर भी रोक

लखीमपुर के जिलाधिकारी ने किसानों द्वारा गर्मी में उगाए जाने वाला सादा धान पर भी रोक लगा दी है। किसान जनवरी-फरवरी माह में महज 60 दिनों में तैयार होने वाली धान की इस किस्म को लगाते हैं। पंजाब में इस पर पहले ही रोक लगाई जा चुकी है, जबकि लखीमपुर, पीलीभीत में किसान इसे आज भी लगाते हैं। चूंकि, इस मौसम में बारिश नहीं होती, इसलिए भूजल का अंधाधुंध दोहन कर इसकी सिंचाई की जाती है। जिलाधिकारी लखीमपुर ने आदेश में कहा है कि किसान भूजल स्तर की चिंताजनक स्थिति को देखते हुए सादा की जगह खीरा, तरबूज, ककड़ी व खरबूते की खेती करें।

क्या कहते हैं विशेषज्ञ

डॉ. वेंकटेश दत्ता कहते हैं कि गोमती के कैचमेंट की बात करें तो उद्गम स्थल माधोटांडा से जौनपुर, जहां गोमती गंगा में मिलती है, जबर्दस्त अतिक्रमण है। नदी भूमि के चिह्नितकरण से मरती हुई नदी को जीवन मिलेगा।

IV | दैनिक जागरण लखनऊ, 15 जनवरी 2017

टेक्नोलॉजी बेस्ड सरकारी योजनाएं ही सफल



आधार कार्ड योजना की सफलता में है प्रौद्योगिकी का बड़ा योगदान

- शोध वही जिससे आमजन का जीवनस्तर सुधरे
- डीएसटी नीति अनुसंधान केंद्र की सिफारिश

जागरण संवाददाता, लखनऊ : आमजन के जीवन स्तर को सुधारने के लिए सामाजिक परिवर्तन से जुड़ी योजनाओं में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का तड़का लगाना जरूरी है। देखा गया है कि बायोमीट्रिक हो, फाइबर ऑप्टिक्स हो, 4 जी हो या आधार कार्ड योजना यह इसीलिए सफल रही क्योंकि इनमें प्रौद्योगिकी का समावेश था। वहीं, इसके विपरीत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा) जो कि सामाजिक परिवर्तन की विश्व की अब तक की सबसे बड़ी योजना है शायद इसीलिए विफल रही क्योंकि इसे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से नहीं जोड़ा गया था।

यह मानना है अंबेडकर यूनीवर्सिटी स्थित डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (डीएसटी) नीति अनुसंधान केंद्र का। केंद्र समंवयक डॉ. वेंकटेश दत्ता द्वारा केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय को भेजी अपनी रिपोर्ट में यह कहा गया है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को लैब से निकाल कर लैंड तक पहुंचाना होगा। उन्होंने कहा कि चिंताजनक यह है कि भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी फिलहाल हाशिए पर जहां सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का मात्र 0.09 फीसद है। वहीं दूसरी ओर चीन, कोरिया, जापान, जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस जैसे देश जीडीपी का दो से तीन फीसद तक खर्च कर रहे हैं।

डॉ. दत्ता के अनुसार यहां वैज्ञानिक समुदाय जो शोध कर रहे हैं उसका सीधा सरोकार आमजन से है ही नहीं। होना यह चाहिए कि शोध एवं विकास के केंद्र में आम आदमी ही हो। यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सामाजिक

रही है वह बगैर रिसर्च एंड डेवलपमेंट मुमकिन नहीं। टेक्नोलॉजी किस तरह सामाजिक विषमता समाप्त करती है इसका उदाहरण मेट्रो है। मेट्रो में सवार होने वाला दूधिया हो या कोई सीईओ वह मेट्रो यात्री (ट्रैवलर) ही

युवाओं के मापदंड भिन्न

देश में दो तिहाई आबादी 25 वर्ष से कम आयु वर्ग की है। उसके लिए जाति, धर्म बेमानी है। उसे तो बस गुणवत्तापरक जीवन की दरकार है। टेक्नोलॉजी को तरजीह देने वाले देशों में सामाजिक विषमताएं फिलहाल हाशिए पर पहुंच चुकी हैं। विदेशों में ही नहीं देश के महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात व कर्नाटक जैसे राज्यों ने भी टेक्नोलॉजी का दामन थाम तरक्की के नए झंडे गाड़े हैं।

उद्योग जनहित में करें शोध

सरकारी क्षेत्र में जहां रिसर्च एंड डेवलपमेंट में धनराशि कम खर्च की जा रही है। दूसरी तरफ उद्योग उन्हीं शोध कार्यों में रुचि लेते हैं जिसमें उनका व्यावसायिक हित जुड़ा होता है। मंत्रालय को दी गई सिफारिश में यह कहा गया है कि उद्योगों के लिए यह अनिवार्य किया जाए कि वह जन सामान्य से जुड़े शोध को भी तरजीह दें।



'कृषि में गुणवत्ता के लिए जल संचय जरूरी'

■ **एनबीटी, लखनऊ :** हमें खेती में ऐसी प्रणाली विकसित करनी चाहिए जो जैव विविधता को बढ़ाने वाली मिट्टी को समृद्ध करने वाली हो। यह बात वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ साइंस के प्रो. रिचर्ड थॉमस ने कही। वह बुधवार को बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय (बीबीएयू) में हुए सेमीनार में शामिल हुए।

डिपार्टमेंट ऑफ साइंस ऐंड टेक्नॉलजी सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च और स्कूल ऑफ इनवाइरनमेंटल साइंस की ओर से हुए सेमीनार में उन्होंने कहा कि कृषि में गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए जल संचायन पर हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तहल ग्रुप के सलाहकार रविंद्र कुमार ने रामगंगा नदी के बेसिन के जल संसाधनों के प्रबंधन के बारे में बात की। प्रो. नवीन अरोड़ा ने कहा कि प्रदूषण को कम करने और जैविक संसाधनों को बढ़ाने के लिए काम करने की जरूरत है।

खेती की गुणवत्ता बढ़ाने को जल संचयन जरूरी

खेती की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जल संचयन अति आवश्यक है। इसके साथ ही खेती में ऐसी प्रणाली को विकसित करना होगा जो जैव विविधता को बढ़ाने वाली मिट्टी को समृद्ध कर सके। यह बातें बुधवार को बीबीएयू में आयोजित कृषि सेमिनार में सिडनी विवि के प्रोफेसर रिचर्ड थॉमस ने कही।

सेमिनार का आयोजन पर्यावरण विज्ञान विभाग की से किया गया। उन्होंने कहा कि अच्छी खेती के लिए तूफान, जल संचयन, वेटलैंड्स, फॉर्म प्लानिंग जैसे बिंदुओं पर हमें ध्यान देना होगा। प्रो. रिचर्ड ने कहा कि तकनीक का इस्तेमाल करके भी हम खेती को विकसित कर सकते हैं। इस दौरान प्रो. नवीन अरोड़ा ने कहा कि प्रदूषण को कम करने और जैविक संसाधनों को बढ़ाने के लिए काम करने की जरूरत है।

युवाओं को प्रयोग के भरपूर अवसर मिलें



बीबीएयू में बिल्डिंग नेशनल एसआईटी पॉलिसी सिस्टम एंड गवर्नेंस फॉर इफेक्टिव आरएंडडी इकोसिस्टम पर कार्यशाला शुरू हुई।

कार्यशाला

लखनऊ | निज संवाददाता

विज्ञान में युवाओं की रुचि पैदा करने के लिए एक नीति बनाने की जरूरत है। इस दिशा में हमारा एक प्रयास यह हो सकता है हम टिंकरिंग लैब्स का निर्माण करें। इसमें युवाओं को उनकी मर्जी और रुचि के अनुसार प्रयोग करने का अवसर दें। यह सुझाव बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर केन्द्रीय विश्वविद्यालय (बीबीएयू) के कुलपति प्रो. संजय सिंह ने मंगलवार को दिया।

वह बीबीएयू के डीएसटी सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च द्वारा बिल्डिंग नेशनल एसआईटी पॉलिसी सिस्टम एंड गवर्नेंस फॉर इफेक्टिव आर एंड डी इकोसिस्टम विषय पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि टिंगरिंग लैब्स में खुद की सोच से नया आविष्कार और प्रयोग छात्र करेंगे तो उनमें आगे कुछ नया तलाश करने की दिलचस्पी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि छात्रों के साथ साथ ऐसे लोग जिनकी विज्ञान में, कुछ नया तलाशने में रुचि है, उनको भी अवसर दिए जाएं। ताकि हम सीमाओं से बाहर निकल कर बड़े पैमाने पर वैज्ञानिक सोच विकसित कर सकें। जिससे लोगों का विज्ञान में रुझाव बढ़े।

जोखिम से तकनीक विकसित होगी

सीएसआईआर के निदेशक डॉ. अलोक धवन ने कहा कि विज्ञान, नवाचार और तकनीक की नीति तब कारगर है, जब हम जोखिम उठाएंगे। नई तकनीक तभी विकसित होगी, जब हम नई सोच के साथ जोखिम उठाएंगे। हमे अलग सोच को एक मौका देने की जरूरत है। जितने भी बड़े देश है, वहा विज्ञान को लेकर अलग प्रयास देखने को मिलता है। छात्र अपनी प्रारंभिक शिक्षा के दौरान ही प्रयोग करते हैं और सीखते हैं।

जल्द लागू हो बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम

केंद्रीय जल आयोग

लखनऊ | वरिष्ठ संवाददाता

केन्द्रीय जल आयोग की ओर से शुक्रवार को ऊपरी गंगा बेसिन संगठन ने ह्यबाढ़, बाढ़ क्षेत्र और उसके वर्गीकरणह्न विषय पर कार्यशाला का आयोजन इंदिरानगर स्थित यूपी कॉपरेटिव लमिटेड एग्रीकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में किया। जिसमें वक्ताओं ने उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की कि वे बिना समय गंवाए बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम लागू करें। जिससे प्रदेश की गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती और सरयू जैसी अन्य नदियों को बचाया जा सके।

केन्द्रीय जल आयोग की ऊपरी गंगा बेसिन संगठन की उप निदेशक दीप्ती वर्मा ने बताया कि कार्यशाला में वैज्ञानिकों और वक्ताओं ने बाढ़, बाढ़ क्षेत्र और उसके वर्गीकरण के फायदा और नुकसान की जानकारी दी। बताया कि बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम लागू किया जाता है तो बाढ़ क्षेत्र में अतिक्रमण कर मकान नहीं बन पाएंगे और जान-माल की हानि भी नहीं होगी। इस अवसर पर केन्द्रीय जल आयोग ने जो काम नदियों के बचाव के लिये किये हैं उसकी भी जानकारी दी गई।

मुख्य अतिथि केन्द्रीय जल आयोग के चेयरमैन आरके जैन रहे। एनआईएच रुड़की के निदेशक एसके जैन के अलावा कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। कार्यशाला में वक्ताओं ने कहा कि बाढ़ का जितना क्षेत्र हैं उसका वर्गीकरण होना चाहिये। उत्तर प्रदेश ने अभी बाढ़ मैदान क्षेत्र का सीमांकन तक नहीं किया गया है। यही कारण है कि नदी के तटीय इलाके मानसून के समय बाढ़ से प्रभावित हो जाते हैं। अगर सीमांकन हो तो समय से पूर्व इससे होने वाले नुकसान से निपटा जा सकता है। इसके लिए हर उपाय करना जरूरी है।

कार्यशाला

- 'बाढ़, बाढ़ क्षेत्र और उसके वर्गीकरण' विषय पर कार्यशाला में उठी मांग
- इंदिरानगर में यूपी कोआपरेटिव लिमिटेड एग्रीकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हुआ आयोजन

कानून बन जाने से नदियों को नया जीवन

अम्बेडकर केन्द्रीय विश्वविद्यालय लखनऊ के पर्यावरण विज्ञान के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. वेंकटेश दत्ता ने बताया कि राज्य स्तर का कानून बन जाने के बाद प्रदेश की नदियों को जीवन मिल जायेगा। भविष्य में कोई अतिक्रमण नहीं हो पायेगा और इसी जमीन पर भूजल भी विकसित होगा। कार्यशाला में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार के अधिकारी मौजूद रहे। बाढ़ क्षेत्र के सीमांकन, नदी का पर्यावरणीय सिस्टम सुधारने, बाढ़ क्षेत्र का विकास करने पर, सेटेलाइट डाटा बनाने के भी सुझाव दिये गये।



विज्ञान के विकास से समृद्ध होगा देश

लखनऊ। बीबीएयू में आयोजित कार्यक्रम में कुलपति प्रो. संजय सिंह ने कहा कि हमें विज्ञान का प्रयोग इस तरह से करना होगा कि हमारी प्रकृति सुरक्षित रहे। कार्यक्रम को पुनर्वास विवि के कुलपति प्रो. राणा कृष्णपाल सिंह, केजीएमयू के डॉ. आरएन श्रीवास्तव, विज्ञान भारती के सचिव डॉ. श्रेयांश मंडलोई, डॉ. वेंकटेश दत्ता ने भी संबोधित किया। वहीं पुनर्वास विवि में विज्ञान प्रदर्शनी लगी जिसमें विद्यार्थियों ने दिव्यांगों के लिए बनाई गई ब्लाइंड डेफ कम्युनिकेटर, हाइड्रोलिक ब्रिज आदि का प्रस्तुतीकरण किया। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (आईईटी) के डिपार्टमेंट ऑफ बायो टेक्नोलॉजी विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में निदेशक प्रो. एचके पालीवाल की मौजूदगी में विद्यार्थियों के बीच प्रतियोगिताएं हुईं। इरम गर्ल्स डिग्री कॉलेज में विज्ञान प्रश्नोत्तरी व विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। एलयू के स्टेटिक्स डिपार्टमेंट में रक्तदान शिविर में विद्यार्थियों व कर्मचारियों ने रक्तदान किया। कुलपति प्रो. एसपी सिंह ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। ब्यूरो



8 दैनिक जागरण लखनऊ, 21 जुलाई 2018

राष्ट्रीय भूजल कानून बनाए जाने की मांग

जागरण संवाददाता, लखनऊ : भूजल का जिस तरह से दोहन हो रहा है उसके लिए जरूरी है कि राष्ट्रीय भूजल कानून बनाया जाए। दरअसल, भूजल के लिए पूरे देश में कोई प्रवर्तन एजेंसी ही नहीं है। यह स्थिति तब है जबकि भूजल पर अर्बन, ग्रामीण, इंफ्रास्ट्रक्चर व कृषि क्षेत्र में भूजल पर 70 से 80 फीसद निर्भरता है। ग्राउंड वॉटर एक्शन ग्रुप की बैठक में विशेषज्ञों ने यह विचार रखे। ग्रुप सदस्यों ने चिंता जाहिर की कि एक अध्ययन के अनुसार केवल उत्तर भारत में हर साल 54 घन किलोमीटर भूजल का दोहन किया जाता है। साफ है कि भूजल भंडारों की स्थिति किस कदर खराब है। ग्रुप के समन्वयक आशुस सिन्हा ने कहा कि भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा जो वॉटर इंडेक्स जारी किया गया है वह काफी चिंताजनक है। आपूर्ति के मुकाबले दो गुना पानी का विकास किया जा रहा है जो कि चिंताजनक है।

ग्रुप सदस्यों के मांग की कि राष्ट्रीय भूजल कानून बनाया जाए। शहरों व ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग-अलग प्रावधान रखे जाएं। कानून में भूजल का मूल्य निर्धारण भी किया जाए। विशेषज्ञ इस बात पर भी एकमत दिखे कि वर्ष 1986 में बनाए गए इंडियन ईजमेंट एक्ट जिसमें यह प्रावधान है कि जिसकी जमीन उसका पानी को तत्काल समाप्त किया जाए। ड्रिप व स्प्रिंकलर इरीगेशन को छोटी जोत के काश्तकारों के लिए सामुदायिक स्तर पर लागू किया जाए। बैठक में पीआर चौरसिया, बॉबी त्रिवेदी, फारूक रहमान खां, डॉ. वेंकटेश दत्ता, पीके श्रीवास्तव, उदय पांडेय, डॉ. विभूति राय, अंशुमाली शर्मा शामिल थे। ग्रुप बैठक की संस्तुतियों को भारत सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार को भेजेगा।

चेक डैम रोक रहे प्रवाह

जल संचयन के लिए नदियों पर बनाए जा रहे चेक डैम से सिल्ट एकत्र हो रही है जिससे नदियों का प्राकृतिक प्रवाह रुक रहा है। इस पर विचार की जरूरत है।

चुनौती बनेगी बढ़ती मांग

पूर्वी उत्तर प्रदेश को यदि छोड़ दिया जाए तो बाकी जगह औसत से कम बारिश हो रही है ऐसे में भविष्य में मांग के अनुसार आपूर्ति बड़ी चुनौती बनेगी। इस पर गंभीर कदम उठाए जाने की जरूरत है।

तालाब बचा लें तो नहीं होगी पानी की कमी

रूपा सिंह, लखनऊ

आज भी गर हम तालाब और पेट तैयार बना दें तो पानी की कोई कमी नहीं होगी। यही नहीं, बारिश के पानी को भी जहां तक संभव हो रोकना होगा। इसके अलावा ऐसा कानून लाए जाने की भी सख्त जरूरत है जिससे जिसकी जमीन उसका पानी के अधिकार को खत्म किया जा सके।

यह बोले खाद्य सलाहकार भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के एंवायरमेंटल स्कूल ऑफ साइंसेज के प्रोफेसर डॉ.वेंकटेश दत्ता ने कही। डॉ. दत्ता दैनिक जागरण कार्यालय में आयोजित 'जागरण विमर्श' कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विडंबना यह है कि अभी तक हमने जल प्रबंधन के तहत केवल सप्लाई पर ही ध्यान दिया, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दे सके कि बाल्टी में छेद है ऐसे में जब तक उसे बंद नहीं किया जाता पानी का रुकना मुश्किल है।

विशेषज्ञ की बात

- संकट से बचने को वाटर सेंचुरी बनाए जाने की जरूरत
- अभी तक जल प्रबंधन के तहत केवल सप्लाई पर ही ध्यान



डॉ. वेंकटेश दत्ता

डॉ.दत्ता ने कहा कि जहां तक जलवायु परिवर्तन की चर्चा हो रही है लेकिन वैज्ञानिक तापमान में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आया है। दरअसल माइक्रोक्लाइमेट चेंज का असर सीधा पड़ता है। यदि हर गांव में तालाब हो तो पानी की कमी नहीं होगी। तालाब खत्म हुए और साथ ही जल संचयन की परंपरागत तकनीक भी समाप्त हो गई। नतीजा जल संकट के रूप में हमारे सामने है।

भूजल सेंचुरी बनें : उन्होंने कहा कि गंभीर समस्या यह है कि बारिश के रूप में जो मीठा जल हमें मिलता है उसे रोक पाने में असफल रहे हैं जिससे यह खारे पानी में तब्दील हो जाता है। अमेरिका-यूरोप ने सतह-आपसी के दशक में ही भूजल सेंचुरी बनाई गई। वहां ऐसा क्षेत्र जहां रीचार्ज जोन है वहां क्षेत्र को इस तरह से संरक्षित कर दिया गया जिससे रीचार्ज बेहतर बना रहे। इसके विपरीत हम अपने खुले कुएपानी को भी कंक्रीट से बदल रहे हैं। यही नहीं विदेशों में

जरूरी है कानून



जागरण विमर्श

जमीन की कीमत डिनेटिंग बढ़ती जा रही है, लेकिन इसके नीचे जो भूजल है उसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं। जरूरत इस बात की है कि कानून बनाकर जमीन के भूजल को अलग किया जाए। भले ही इसके लिए संसद बनाना पड़े। उन्होंने कहा कि 1950-60 के अभिलेखों के अनुसार राजधानी में लगभग हजार तालाब थे। जबकि आज गिने-चुने तालाब ही बचे हैं। आज जहां अतिक्रमण तालाबों, सड़क सिटी है वह अभिलेखों में जल प्लावित क्षेत्र के रूप में दर्ज है। जबकि है कि तालाब जमीन के तालाब की पेट कट गए। उन्होंने 'जागरण' द्वारा तालाबों को बचाने के लिए चलाए जा रहे अभियान की प्रशंसा करते हुए कहा कि अभी भी देर नहीं हुई है।

यह करना जरूरी

- जल संरक्षण के वर्तमान स्रोतों को अभिलेखों में निश्चितकर चिन्हित कर और उन्हें पुनर्जीवित किया जाए।
- तिलमनें को पानी के प्रबंधन के लिए में प्रशिक्षित किया जाए ■ पानी का सैंपल लेने वाले पेय ऑपरेटरों को प्रशिक्षित कर उन्हें पानी का मोल बताया जाए
- लोग घरों में टोंटी में अवश्य सिस्टर लगाएं और पानी बर्बाद होने से रोकें ■ जल प्रबंधन का ज्ञान देने वाले शिक्षणों में आपदा समयता को बढ़ावा जाए
- नदी जोड़ो परियोजना के बजाय इंटर बेसिन वॉटर ट्रांसफर योजना लागू की जाए

आईपीसीसपार एवमूल्यन तक बनाए गए है।

रिवर फ्रंट भारत के लिए मुफीद नहीं : उन्होंने गोमती रिवर फ्रंट के नाम पर नदी के साथ हो रहे खिलवाड़ पर भी नियमा जाहिर की। उन्होंने कहा, पहले नदी के किनारों पक्का कालस किर उसमें दुबारा नदी से पानी पहुंचाना नहाक दिखावा है। नदी अधिनियम के तहत नदी के दोनों ओर 500 मीटर कंक्रीट का इलेमेंटर प्रतिबंधित है। आप खुद सोचिए जब किनारे पक्के होंगे तो कछुए अंडे कहां देंगे।

वजूद कायम लगभग 500 साल पुरानी है ऐशबाग में कब्रिस्तान और श्मशान घाट के बगल में मौजूद जमुना झील

गूगल मैप में महफूज हैं जमुना झील के निशां

रूपा सिंह ● लखनऊ

ऐशबाग स्थित जिस जमुना झील के अस्तित्व पर आज सवाल खड़े किए जा रहे हैं उसके निशां सेटेलाइट चित्रों में महफूज हैं। गूगल मैप में जमुना झील को साफ तौर पर देखा जा सकता है। झील की परिधि लगभग 1.8 किलोमीटर है। ऐशबाग में कब्रिस्तान व श्मशान घाट के बगल में मौजूद जमुना झील लगभग 500 साल पुरानी है। इसका पुराना नाम जमुनिया झील था जिसे बाद में जमुना झील कहा जाने लगा।



गूगल मैप पर दिख रही जमुना झील

- कभी जमुनिया झील कही जाती थी, परिधि लगभग 1.8 किलोमीटर
- 2006 में सुंदरीकरण का बना था प्रस्ताव
- बीच में ही काम रुकने से दूर नहीं हो सकी झील की बदहाली

अंबेडकर विश्वविद्यालय के पर्यावरण विभाग के प्रोफेसर डॉ. वेंकटेश दत्ता बताते हैं कि दरअसल जमुना झील मोती झील का ही हिस्सा थी जो बाद में अलग हो गई थी। वर्ष 2006 में झील के सुंदरीकरण का प्रस्ताव भी बनाया गया था। करीब 12 करोड़ रुपये खर्च कर घाट बनवाने के साथ पानी को साफ करने के लिए मशीन भी मंगवाई गई लेकिन काम पूरा होने से पहले ही बीच में रुक गया और झील की बदहाली दूर न हो सकी।

जल संस्थान के पूर्व महाप्रबंधक राजीव वाजपेयी बताते हैं कि मोती झील व जमुना झील एक ही हैं। इसमें आसपास का सीवर जाता था जिसे पाइप डालकर लेबर फालोनी के पास नाले में डायवर्ट किया गया। वहीं नहीं, ऐशबाग जलकल के बैक वाश का पानी भी झील में जाता था। झील के सुंदरीकरण की योजना बनी तो जल निगम ने इस पानी को साफ कर झील में डालने की योजना बनाई। वहां प्लांट भी लगाया गया लेकिन योजना सफल नहीं हुई। दूसरी तरफ झील की स्थिति और भी खराब होती गई।

शहर की अन्य झीलें भी संकट में : डॉ.वेंकटेश दत्ता कहते हैं कि जमुना झील ही नहीं शहर की अन्य झीलें भी अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रही हैं। कैपवेल रोड और मोहन रोड के बीच स्थित काला पहाड़ झील अतिक्रमण का शिकार है। रायबरेली रोड स्थित झील के सुंदरीकरण का काम एलडीए ने शुरू किया था। कुछ समय बाद काम बंद हो गया। आज झील बदहाल है।

तेलीबाग में विनायक झील गंदगी और मलबे से भरी है। एल्डिको उद्यान दो में करीब एक किमी लंबी झील बनवाई गई थी जो आज नाले में तब्दील हो चुकी है। डालीबाग के बटलर पैलेस झील की स्थिति भी बदतर होती जा रही है। हैदतमऊ मवैया झील अतिक्रमण का शिकार है। हैदतमऊ मवैया झील के चारों ओर कब्जा हो चुका है।

The process to choose the best suited model for a truly green Lucknow was gruelling as much as it was enlightening. The diverse and innovative ideas for sustainable development opened up possibilities of an eco-friendly city of the future, with the judges hoping authorities would take notice

Of gigantic models, judges' tips, youth out to save a city

Times News Network

So, it is the process of methuselah that would achieve that?" asked one of judges. "Yes sir," said a student, nervous but eyes shining with enthusiasm.

If you thought this was a classroom, you are right, virtually. With the TOI office on Friday teeming with students and teachers running around with massive science models, it appeared more like a school bhi than a newspaper office.

It was the day when models for the TOI Green Parliament was finally judged, with our eminent panel – environmentalist Venkatesh Dutta, geologist Dhruv Sen Singh and educationist Amrita Dass – asked questions, debated and even provided valuable inputs to students.

It was, on one hand, tough getting past them while on the other like a classroom with three teachers disseminating knowledge with enthusiasm and bit of cuts.

So, when a young student from La Martiniere College focused more on the social aspect of her idea of cleaning the Radha Ghat along river Gomti and talked about using a support group to make a change, Dass was elated and asked editors of TOI to support her cause by spreading the message.

Some came with gigantic models while others made their point with small, compact ones. And, it was a competition where nobody was a loser, and all students took back learnings from the information exchanged by the judges.

The judging exercise became a learning process for participants as the judges advised the students, even on how to make presentations in future, apart from guiding them on various subjects.

> Models presented by students were innovative and original. The students had thought well for making Gomti river a neat, clean and sustainable river. Use of renewable energy resources was well depicted in the models
> **Dhruv Sen Singh**

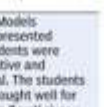



> The students were exceptionally bright and had genuine interest to make Lucknow a green city with several eco-friendly ideas. The smart city concept should be ingrained and authorities should work on these services
> **Venkatesh Dutta**



> The models prepared by the students were impressive and their passion infectious. Each team had thought of some innovative and feasible ideas on green sustainable projects. If some of these ideas are implemented, Lucknow and its neighbouring areas would certainly pioneer some of the global best practices of a SMART city
> **Amrita Dass**



The judging exercise became a learning process for participants as the judges advised the students on how to make presentations in future, apart from guiding them on various subjects

Their ideas can usher change

TOI takes a peep into the models, and the minds of students who made them. Today, we present the third and fourth place winners

Only felt hunger for success

The unique idea of converting plastic wastes into energy is interesting. This could be a way to alleviate both landfill and energy woes together. The model can be tried on some small industries where carbon emissions can be captured to convert into energy. The plastic wastes can be burned under controlled conditions to generate heat and steam. Steam can power a small turbine to produce electricity. The ash and carbon left can be used in making roads

Venkatesh Dutta |



A hour before they were about to leave school for summer vacations, Swechchha Singh and Aditya Singh, were called out from their classrooms by one of their teachers.

"We were afraid as we thought we have done something wrong and will be punished. But then we met the principal who told us that we have been selected to make a model on Green Lucknow. Both of us were on cloud 10," said Aditya, a class X student of Lucknow Public College.

The two only had four days to prepare their model and as they stopped doing everything else and concentrated on their model. "We took guidance of our teacher. All we wanted was to design a unique model so that we can present ourselves before the CBI. And we did it," said Swechchha.

For the duo who gathered at the school to prepare the model, finding an idea was not a problem.

Falling short of time, they worked continuously for 10 hours a day, sometimes without realizing that they were hungry.

"We were so excited that one day, it was not until 4pm that we realized that we had not eaten anything. Both of us then rushed to a shop outside and bought food," recalled Aditya.

A live demo created magic

Demonstrating a live chemical reaction in front of the judges, class X students Swechchha Singh and Aditya Singh came up with the innovative idea of generating electricity from treating waste plastic.

According to them, the gas produced during heating of waste plastic could be used to produce electricity. This way, plastic will not pollute the environment. While waste plastic made roads are in use in many cities, the gas produced during the heating is often released in the air which pollutes the environment.

The duo suggested that the gas could be mixed with water to make carbonic acid, which is charged. They showed this with the help of a mud pot which was used to burn some plastic waste and collected the resultant smoke via a funnel in a glass filled with water. The water (carbonic acid) was charged, which was demonstrated with the help of a cathode and anode connected to a galvanometer. Further, the students demonstrated how the use-residue waste plastic could be used to make roads and how plastic made-roads are more durable than coal tar made roads.

I congratulate TOI for giving such a platform to the students. A lot has been said about the environment but the on ground, activity by locals has not yet been seen. The students who are the city's face are full of ideas to make Lucknow green and clean. They are conceptually better and are much more informative than us

Rupali Patel | PRINCIPAL, LUCKNOW PUBLIC COLLEGE, GOMTINAGAR

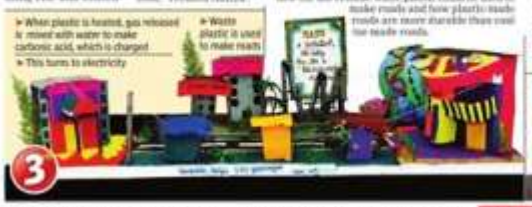

LUCKNOW PUBLIC COLLEGE, GOMTINAGAR | **Swechchha Singh, Aditya Singh**



Perfection in nick of time

This team of five students pulled off a wonder that few do. Their final model, which aimed at effective plastic waste management, was completed in a day. Vipul Singh, team member, blames their indecision for the delay. "We wanted almost a week to finalizing the ideas. On top of that, our model was rejected by our teacher. We were left just with two days to work on another model," said Vipul.

Switching on to the fast and furious mode, students gathered at a friend's place. But the hurdles didn't cease. The students almost lost their chance to present their model in front of the jury.

"While we were trying to fix things, we failed to put a coat of plaster to our plastic house. Since none of us had worked with Plaster of Paris earlier, we couldn't get the mixture right. Either, it was too dry or too wet. The first many trials failed before we could get a right proportion," said Deeptiesa Jaiswar, a team member. But in the end, everything fell into place.

So how did the idea strike them? The idea came out from a news piece which Vipul's father was reading. "While he was reading online, my eyes saw something as 'plastic' and 'management'. That is when I asked him (father) to read the article loudly," said Vipul.

After hours of work everyday, the team members enjoyed themselves by singing songs.

And not to miss, there was always good food served to us by our friend's mother. "Thanks to aunt for keeping our tummies full," said Pragati Bansal, another team member.

A plastic house that won real hearts

Coming up with an innovative idea, this group of students replaced bricks and cement used in construction with waste plastic like cold drink bottles, soda bottles and water bottles. They used these to build a wall and subsequently, a 'plastic house'.

An elegant, simple yet utility model, the students filled these bottles with sand or biodegradable waste and then mixed it with Plaster of Paris to make them sturdy. This plastic house is not only an effective solution to reuse plastic but also stronger as compared to brick houses, and earthquake-resistant.

In their concept, the virtually waste-land plastic bottles were put to the best use possible.

This is an effective solution for reusing plastic, they explained. Students recommended construction of plastic houses on low cost, easy-to-title, and ones that absorbs abrupt shock loads. If the concept caught on, it could massively reduce littering as well as spread of non biodegradable waste in the environment. The concept is presently being used successfully in Uganda and Nigeria, the students said.

We are delighted to see the creativity of children being encouraged to contribute to the city's environment. We look forward to TOI initiating more such exceptional campaigns to inculcate a sense of social responsibility among young ones

Siddharth Kapoor | DIRECTOR, VIDYATREE MODERN COLLEGE



The idea of recycling waste plastic bottles as an alternative building material to bricks appeals to me. While addressing the issue of plastic pollution, this would be a viable and feasible model for low-cost, durable houses for all

Amrita Dass | DELHI PUBLIC SCHOOL, GOMTI NAGAR



THE TEAMS | **VIDYATREE MODERN COLLEGE** | **Pragati Bansal, Vipul Singh, Deeptiesa Jaiswar, Shashwat Lahiri**

गहराते संकट की अनदेखी

विश्व जल दिवस पर डॉ. वेंकटेश दत्ता के विचार

भारत दुनिया में भूजल का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। यहां प्रतिवर्ष लगभग 230 घन किलोमीटर भूजल का इस्तेमाल होता है, जो पूरे विश्व के भूजल उपयोग के एक चौथाई से अधिक है। भारत की 60 प्रतिशत से अधिक सिंचाई एवं 85 प्रतिशत पीने के पानी की आपूर्ति भूजल से होती है। जाहिर है, भूजल घटने से कृषि, खाद्य-सुरक्षा, आजीविका और आर्थिक विकास की स्थिरता पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। पूरे भारत में सिंचाई, उद्योग और घरेलू उपयोग के लिए भूजल एक आसान विकल्प बन गया है। सुलभ होने के अलावा यह एक सस्ता, सुरक्षित और अच्छे गुणवत्ता वाला पानी का स्रोत है, जिस पर नियंत्रण करना बहुत मुश्किल है। शहरों एवं महानगरों में, जल-बोर्डों और नगर निगमों द्वारा अपर्याप्त पानी की आपूर्ति के कारण कई लाख प्राइवेट बोरिंग हो गई और स्थिति तेजी से बिगड़ती जा रही है। मौजूदा चलन जारी रहा तो आने वाले 20 वर्षों के अंदर भारत के 60 प्रतिशत भूजल भंडार की हालत गंभीर हो जाएगी।

> भारत में सिंचाई, उद्योग और घरेलू उपयोग के लिए भूजल एक आसान विकल्प बन गया है। सुलभ होने के अलावा यह एक सस्ता, सुरक्षित पानी का स्रोत है

गंगा का विस्तृत मैदान जो उत्तरी और मध्य भारत के करीब 2000 किलोमीटर में फैला है वह मीठे भूजल का भंडार क्षेत्र है, लेकिन अत्यधिक दोहन के कारण कई विकास खंडों को 'अतिदोहित' क्षेत्र घोषित करना पड़ा है। 2004 में केंद्रीय भूजल बोर्ड ने भारत के विभिन्न राज्यों में 65 अतिदोहित क्षेत्रों को अधिसूचित किया था जहां भूजल के स्तर में बहुत तेजी से गिरावट दर्ज की गई थी। 2011 के आंकड़े के अनुसार देश के विभिन्न राज्यों की कुल 6607 मूल्यांकन इकाइयों में 1071 इकाइयां अतिदोहित हैं, जहां वार्षिक भूजल खपत वार्षिक भूजल उपलब्धता से अधिक है। इसके अलावा 217 इकाइयां 'क्रिटिकल' है जहां भूजल विकास 90 प्रतिशत से ऊपर है। 92 ब्लॉक ऐसे हैं जहां भूजल पूरी तरह से खारा हो चुका है। भूजल के अतिदोहन से समुद्र के किनारे के इलाकों में मीठा पानी खारा हो रहा है।

भारत के अतिदोहित भूजल क्षेत्र ज्यादातर चार राज्यों में बंटे है-पंजाब का उत्तरी पश्चिमी हिस्सा, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। हालांकि यहां भूजल के पुर्नभरणीय संसाधन मौजूद हैं, लेकिन भूजल के अंधाधुंध दोहन से जल-स्तर लगातार नीचे जा रहा है। भारत के पश्चिमी हिस्से में खासकर राजस्थान और गुजरात में शुष्क जलवायु के कारण भूजल रिचार्ज कम हो पाता है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पानी की उपलब्धता कम है और भूजल के भंडार भी कम हैं।

नदी के पानी से भूजल का पुर्नभरण होता है विशेषकर बाढ़ के समय। वहीं जब नदियों का पानी कम होता है तो वही भूजल रिसकर नदी के प्रवाह को बनाए रखता है। सिंचाई के लिए अत्यधिक जल की मांग से भूजल का इतना दोहन हो रहा है कि गांवों में कुएं सूख गए हैं और अब छोटी नदियों-तालाबों और झीलों में सालों भर पानी नहीं रहता है। नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में यदि भूजल का भंडार बना रहे तो नदियों में पानी सालों भर बना रहेगा। इसके लिए हमें सहायक नदियों और नालों पर चेक डैम बनाने होंगे, तालाबों को जीवंत करना होगा और कृषि स्वरूप को बदलना होगा। भारत के अधिक आबादी और आर्थिक रूप से उत्पादक क्षेत्रों में भूजल का निरंतर गिरना आने वाले समय में कई चुनौतियों को जन्म देगा। यथास्थिति को बदलने के लिए तत्काल ठोस कदम उठाने होंगे। हर वाटरशेड में पानी की मूल जरूरतों की पूर्ति के लिए क्षेत्र की क्षमता के अनुसार जल संरक्षण और भूजल रीचार्ज की योजनाओं का क्रियान्वयन करना होगा। तुलमूल रवैये से हमारी कृषि, आजीविका और खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।

देश के कुछ इलाकों में निजी पहल से भूजल संवर्धन और संरक्षण के उपाय किए जा रहे हैं जिससे भूजल की स्थिति में सुधार हो रहा है और बारिश और कैचमेंट प्रबंधन के नए तरीकों से किसानों को फायदा मिल रहा है। आंध्र प्रदेश के किसानों ने स्वेच्छा से अपने पानी का उपयोग कम कर दिया है और सामुदायिक भूजल प्रबंधन के मॉडल विकसित किए हैं। उनकी आय दोगुनी हो गई है और भूजल का उपयोग भी इष्टतम स्तर पर आया है। किसानों को ट्रेनिंग देकर उन्हें सामूहिक संरक्षक बनाया गया है। हमें इस तरह के प्रयास कई विकास खंडों में करने होंगे। बुंदेलखंड के कई किसानों ने अपना तालाब अभियान शुरू भी कर दिया है।

(लेखक सोमती अध्ययन दल से जुड़े हैं)

Stop groundwater misuse, experts urge all parties

Pranchal Srivastava | TNN

Lucknow: Rapid depletion of groundwater levels across the city has prompted a group of water conservationists to appeal to all political parties to give the alarming issue a place on their poll agenda.

Hydrogeologist RS Sinha, former senior engineer General Ground Water Board Ifti Trivedi, environmentalist and BHAU professor Venkatesh Dutta and environmentalist Farukh Rahman Khan, who are all members of the Ground Water Action Group, have in an open letter exposed "the grim situation".

They have claimed "unchecked groundwater use for drinking, agriculture and industrial purpose with little effort to replenish the depleting resources". Laws on groundwater preservation are being blatantly violated, they have said and demanded a dedicated cell for strict monitoring.

According to hydrogeologist Sinha, the ideal groundwater level is 5.8 metres below the surface. But, indiscriminate use has caused the level to plummet up to 14 metres in many places, he pointed out. The situation is alarming because 40% of Lucknow's total 30 lakh population is dependent on groundwater, drawn through tube wells and submersible pumps, to quench their thirst.

Extraction at such a high rate can lead to land subsidence in the future, the experts warned, adding that if the situation went unchecked, there would be no groundwater source left in 8-10 years from now.

Areas where the groundwater level is alarmingly low (below 14 metres) are Gomtinagar, Indiranagar, Janakipuram, Lalbagh, Jail Road, Vrindavan Colony, Mahanagar, Aliganj, Amanabad, Hazratganj, Trivenagar, Ganeshganj and Nazbasta.

The situation is no better across UP with 56 out of 75 districts facing acute water crisis. Some of the districts in red zone are Kanpur (13m), Barabanki (12m), Gonda (12m), Hardoi (11m) and Balrampur (11m).

Meanwhile, the residents of LDA colony in Naka and Rajajipuram have been facing problems of unclean water supply and water-logging during monsoon for the past 10-15 years. "We have been running from pillar to post since years, but nobody listens. Now we will support a candidate who will support us in our cause" said Swati Nigam, a resident.

Bihartial, a resident of Hari Nagar, Balaganj, said, "This colony was built in 1986 and we moved here in 2001. Despite being close to Jal Nigam pumping station, no water supply line has been laid in our colony.

"Few years back, they laid the sewage line but that remains choked. We believe that the matter will be resolved only when candidates seeking elections make it a political issue."

THE DEPTH OF CRISIS

The ideal level of groundwater is 5.8m below surface. The depth at which it is found in parts of Lucknow

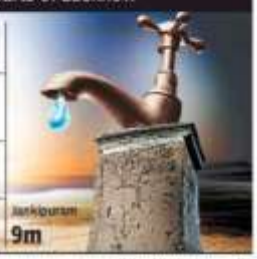

POLL ISSUE

दैनिक जागरण, वाराणसी, 26.12.2019

पूरे बेसिन की चिंता से साफ होगी गंगा

सहायक नदियों को नजरअंदाज करना सबसे बड़ा रोड़ा

रूमा सिन्हा ● लखनऊ

गंगा केवल वही नहीं है जो आंखों से दिखती है। बेशक इसकी धारा गोमुख से फूटती है, मगर जीवन भूगर्भीय जलधाराओं, जलाशयों और सहायक नदियों से ही मिलता है। यही वजह है, पर्यावरणविद गंगा को निर्मल और अविरल बनाने के लिए पूरे बेसिन (घाटी) की चिंता पर जोर दे रहे हैं। अध्ययन में दावा किया है कि सिर्फ गंगा पर अरबों रुपये बहाने से कुछ नहीं होगा। इसे समग्र रूप से देखने और समझने का वक्त आ गया है। गंगा को बचाने के लिए सबसे पहले उसकी सहायक नदियों को जीवंत रखना होगा।

नदियों की स्थिति पर लगातार नजर रखने वाले डॉ. बीआर अंबेडकर यूनिवर्सिटी में पर्यावरण विभाग के प्रोफेसर डॉ. वेंकटेश दत्ता ने गंगा व उसकी सहायक नदियों पर भी विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। यह जानने के उद्देश्य से कि आखिर इसकी सफाई और अविरलता में बाधा क्यां हैं? उनके अध्ययन में वही बातें सामने आई हैं, जिसकी चिंता लगातार जताई जाती रही है। उनके मुताबिक भले ही हम पानी की तरह पैसा बहा लें, मगर देश के 26 फीसद भूभाग में फैले गंगा बेसिन के समूचे जलतंत्र और इससे जुड़े इकोसिस्टम को समझे बिना गंगा को प्रदूषण मुक्त कर पाना असंभव है। सिर्फ सीवेज व औद्योगिक प्रदूषण की रोकथाम से काम नहीं चलेगा। प्रोफेसर दत्ता के मुताबिक, गंगा को अविरल व निर्मल रखने में भूमिगत एक्यूफर्स, सहायक और छोटी नदियों की मुख्य भूमिका है। यह जानते हुए भी योजना में इन्हें स्थान नहीं दिया गया है।



अध्ययन

- सिर्फ गंगा पर अरबों रुपये बहाने से कुछ नहीं होगा
- सिर्फ सीवेज व औद्योगिक प्रदूषण की रोकथाम पर्याप्त नहीं

गंगा सफाई पर खर्च

राज्यसभा में पेश केंद्र सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2014 से जून 2018 तक गंगा नदी की सफाई पर 3,867 करोड़ रुपये से अधिक रुपये खर्च हुए हैं। बताया कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) के तहत राज्य सरकारों को भी वित्तीय सहायता दी गई। करीब 17484.97 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से गंगा की घाटी वाले राज्यों में 105 परियोजनाएं मंजूर की गई है।

गंगा से कुछ तथ्य

- 43 फीसद आबादी का पोषण करने वाला देश सबसे बड़ा नदी बेसिन
- 10 सहायक नदियां गंगा बेसिन में शामिल। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, यमुना, तमसा, सोन, पुनपुन आदि
- 11 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, मध्य प्रदेश में फैला बेसिन
- 01 वृक्ष की शाखाओं की तरह बेसिन का समूचा नदी जलतंत्र व जलधाराएं फैलीं

बेसिन में भूजल के प्राकृतिक प्रवाह की स्थिति

- गंगा बेसिन में भूजल का कुल प्राकृतिक प्रवाह (बेस फ्लो) 15 अरब घन मीटर प्रति वर्ष
- उत्तर प्रदेश- 4.60 अरब घन मीटर
- बिहार- 2.43 अरब घन मीटर
- प. बंगाल- 2.77 अरब घन मीटर
- मध्य प्रदेश- 1.95 अरब घन मीटर

(शेष बेस फ्लो बचे सात राज्यों से आता है)

40 फीसद तक घटा जलप्रवाह: भूवैज्ञानिकों के अनुसार, गंगा व सहायक नदियों का जलप्रवाह भूजल स्रोतों से निरंतर पोषित होता है। अदृश्य भूजल भंडारों से समूचे गंगा बेसिन के नदी तंत्रों को करीब 15 अरब घन मीटर पानी प्राकृतिक रिसाव (बेस फ्लो) के रूप में मिलता है। बढ़ते भूजल दोहन से बीते दशकों में गंगा व सहायक नदियों के जलप्रवाह (ई-फ्लो) में 25 से 40 फीसद तक की कमी आई है। सीवेज के साथ गंगा में प्रदूषण की एक प्रमुख वजह यह भी है। पर्यावरणविद कहते हैं, जब तक भूजल स्रोत का अत्यधिक दोहन नहीं रुकेगा, सहायक नदियों की जलधाराएं नहीं सहेजेंगे तब तक गंगा वास्तविक स्वरूप खोती रहेगी। गंगा बेसिन के तमाम जल स्रोतों में घातक भारी धातुएं जैसे आर्सेनिक, आयरन, कैडमियम, क्रोमियम, मैंगनीज खतरनाक सीमा में पाए गए हैं।

गंगा किनारे 2500 किसान सीखेंगे जैविक खेती के गुर

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : नमामि गंगे योजना के तहत एक जनवरी से शुरू होने वाली गंगा यात्रा में बिजनौर से बलिया तक 27 जिलों में जीरो बजट की प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित किया जाएगा। गंगा नदी के किनारे बसे गांवों के 2,500 किसानों को जैविक खेती के गुर भी सिखाए जाएंगे। इस अभियान में सक्रिय लोक भारती के संपर्क प्रमुख श्रीकृष्ण चौधरी ने बताया कि गंगा के 2071 किलोमीटर के प्रवाह क्षेत्र में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की कार्ययोजना बनी है। अन्य प्रदेशों में भी खेती के प्राकृतिक तरीकों अपनाने की होड़ बढ़ी है। आंध्र प्रदेश में प्राकृतिक कृषि विश्वविद्यालय बनाकर किसानों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। करीब 25 हजार किसान प्रशिक्षित हो चुके हैं। इससे किसानों की आय में भी बढ़ोतरी हुई है। गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए दोनों किनारों पर बसे गांवों में सघन वृक्षारोपण, तालाबों व पोखरों का पुनर्जीवन किया जाएगा।

प्रदूषण की बनेगी कुंडली

जासं, कानपुर: पतितपावनी की निर्मलता, शुचिता और अविरलता लौटाने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने तैयारी शुरू कर दी है। अब जीरो डिस्चार्ज फार्मूले को सफल बनाने के लिए गंगा को दूषित करने वाली इकाइयों की कुंडली तैयार होगी। शोध कर गंगाजल की गुणवत्ता जांची जाएगी। खामियां मिलने पर दूर करने की प्लानिंग तैयार होगी। नमामि शिक्षण संस्थानों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।

जन जागरण परिसंवाद

नीतियों की पड़ताल

समाज के कमजोर और शोषित तबकों के लिए बनाई गई नीतियों की तकनीकी विशेषज्ञों और सरकार द्वारा बतौर क्रियान्वयन एजेंसी पड़ताल की जानी चाहिए। दरअसल, समाज कल्याण के लिए बनाई गई योजनाओं का स्वरूप जरूरतमंद तक पहुंचते-पहुंचते कुछ और ही हो जाता है। लिहाजा, हर योजना के क्रियान्वयन पर निगरानी की जरूरत होती है।

वार्तकार

- संदीप खरे, सामाजिक कार्यकर्ता
- डॉ. अंशुमाली शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता व शिक्षक
- डॉ. वेंकटेश दत्ता, सहायक आचार्य अंबेडकर विश्वविद्यालय
- डीके शर्मा, भू-वैज्ञानिक
- सपना उपाध्याय, सामाजिक कार्यकर्ता

नीति निर्माण में भागीदारी जरूरी

जानें, लखनऊ : समाज के कमजोर तबके को मदद मुहैया कराने वाली नीतियों की कमी नहीं लेकिन यह ऊपर से थोपी नीतियां हैं। जरूरत है कि नीति निर्माण में लोगों को शामिल किया जाए, इनके क्रियान्वयन की मॉनीटरिंग हो, सोशल ऑडिट किया जाए, अधिकारों की जिम्मेदारी तय हो और अमलकल रहने पर सख्त एक्शन हो तभी इनका वास्तविक फायदा मिल सकता है। जरूरत इस बात की भी है कि योजनाओं का लाभ वास्तविक लाभार्थी को मिले, जिन्हें योजनाओं की जानकारी नहीं उन तक जानकारी पहुंचाई जाए। यह विचार रविवार को दैनिक जागरण कार्यालय में जन जागरण अभियान के तहत आयोजित परिचर्चा में उभर कर आए-



सपना उपाध्याय, सामाजिक कार्यकर्ता

• हर योजना की मानीटरिंग का तंत्र मजबूत होना चाहिए। अंतिम लाभार्थी की सीधी सुनवाई होनी चाहिए।
• योजना को लागू कराने वालों की जिम्मेदारी का निर्धारण होना चाहिए। साक्ष्यों के आधार पर परीक्षण होना चाहिए।
• वही योजनाएं (मसलन पोलियो उन्मूलन) सफल रही जिनकी लगातार निगरानी हुई। उनके परिणामों की निरंतर समीक्षा की गई।
• सोशल आडिट सिस्टम प्रभावी और बुस्तैद होना चाहिए। योजना का परीक्षण अंतिम लाभार्थी स्तर से किया जाए कि उस तक लाभ पहुंचा कि नहीं।
• योजना का प्रचार -प्रसार प्रभावी तरीके से किया जाए ताकि बिचौलियों की जरूरत ही नहीं पड़े। जब लोगों को योजना व लाभ की जानकारी होगी तो वे स्वत: जागरुक होंगे।



डॉ. वेंकटेश दत्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, अंबेडकर विश्वविद्यालय

• योजनाओं को बनाते वक्त ही वास्तविक आंकड़ों, उसमें लीकेज आदि का परीक्षण होना चाहिए। ताकि लाभ अधिकतम लोगों तक पहुंच सके।
• योजना को लागू करने में कई विभागों के बीच में कोई तालमेल नहीं होता, जिससे अपेक्षित फल भी नहीं मिलता। जरूरी है कि योजना को लागू करते वक्त ही निगरानी का इंतजाम किया जाए।
• योजना लागू करते समय यह तय नहीं होता कि उसमें काम करने वाले लोग कौन होंगे। विभागों में कर्मचारी है नहीं, संविदा कर्मियों के भरोसे योजनाओं पर काम कराया जाता है।
• योजना के लिए जिम्मेदार लोगों का दायित्व तय नहीं होता। निगरानी भी नहीं होती। नतीजा यह होता है कि योजना का सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं होता।



संदीप खरे, सामाजिक कार्यकर्ता

• संविदा आधारित लोगों के जरिए लाभकारी योजनाओं पर काम किया जाता है। इन लोगों की जिम्मेदारी भी तय नहीं होती। नतीजतन योजना का लाभ भी लोगों को नहीं मिलता।
• सामाजिक स्तर में सुधार के लिए बजट में होने वाले व्यय तथा व्यावसायिक प्रमोशन के लिए आवंटित बजट में अंतर से ही शीर्ष नेतृत्व की मंशा साफ हो जाती है।
• व्यक्ति केंद्रित योजनाओं का चेहरा तो मानवीय होता है लेकिन जिस्म अमानवीय। कारण है कि योजना को लागू करते समय वास्तविक स्थितियों का सही आंकलन तक नहीं किया जाता।
• योजनाओं के नाम पर भी समाज में भेद कर दिए गए हैं। अलग अलग वर्गों के लिए अलग योजनाएं। इससे भी योजनाएं असफल हो जाती है।



अंशुमाली शर्मा शिक्षक एवं सामाजिक कार्यकर्ता

• नीति का निर्धारण करने वालों की नीयत ही ठीक नहीं होती। नीति बना दी जाती है तो उसका क्रियान्वयन नहीं किया जाता।
• योजनाओं का सोशल आडिट नहीं होता। जबकि सोशल आडिट के जरिए योजनाओं का मूल्यांकन -अनुश्रवण किया जाना चाहिए।
• योजना को लागू कर दिया जाता है लेकिन प्रशासनिक ढांचा मजबूत करने पर काम नहीं होता। नतीजतन योजनाओं में तमाम खामियां पैदा हो जाती हैं।
• योजना का काम निर्बल वर्ग को सशक्त करना होना चाहिए। न कि उन्हें आश्रित करना।
• विभिन्न स्तरों पर योजनाओं के क्रियान्वयन का परीक्षण होना चाहिए। जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। तभी योजना से सभी को लाभ मिलेगा।



डीके शर्मा भू वैज्ञानिक (से नि.)

• एक व्यक्ति द्वारा अचानक नीति तय कर दी जाती है, योजना बनती है लेकिन वास्तविक आंकड़े तक नहीं रहते।
• कल्याणकारी योजना में लाभार्थी की भागीदारी तय होनी चाहिए। इसके अलावा योजना लागू करने वालों की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए।
• योजनाओं में भ्रष्टाचार का दीमक लग चुका है। पात्रों तक लाभ नहीं पहुंच रहा है लेकिन भ्रष्टाचार की सुनवाई के लिए भी कोई तंत्र नहीं है।
• कल्याणकारी योजनाओं का पैसा वित्त वर्ष के अंतिम दिनों में ही खर्च किया जाता है। ऐसे में पैसा वास्तविक पात्र तक पहुंचना अपने आप में मुश्किल होता है।
• योजना को लागू करने के साथ ही उसकी प्रभावी मानीटरिंग की भी व्यवस्था होनी चाहिए। ताकि अंतिम कड़ी तक योजना का लाभ पहुंच सके।